कटघरे में सरकार

प्रभात कुमार रॉय

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सन 1977 के आम चुनाव के ऐतिहासिक सबक को कांग्रेस ने पूर्णतः विस्मृत कर दिया है। कांग्रेस ऐतिहासिक सबक को विस्मृत न करती तो यकीनन उसकी यूपीए सरकार 4 जून 2011 की काली रात में रामलीला मैदान में सोये 50 हजार अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर इतने बर्बर और वहशियाना तरीके से कदाचित प्रहार न करती। किसी पूर्व चेतावनी के बिना, केंद्रीय हुकूमत के सीधे नियंत्रण में कार्यरत दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोलों को दागती हुई, लाठियां और बंदूकें लेकर हजारों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर टूट पड़ी। पूर्णतः अहिंसक विरोध प्रदर्शन का ऐसा ही हश्र किया जाएगा तो नक्सलियों का प्रभाव बढ़ने का खतरा भयानक तौर पर बढ़ सकता है। शर्मनाक स्थिति तब और विकट हो जाती है जबकि कांग्रेस नेतृत्व अपने कुकृत्य पर शर्मिंदा होने और पश्चाताप करने के स्थान पर बेशर्मी के साथ उसकी पैरोकारी करते नजर आता है। विदेशों में काले धन के तौर पर संग्रहित किए अकूत अरबों-खरबों की धन राशि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अहिंसक आंदोलन क्या गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने शानदार ढंग से सारे मामले का संज्ञान में लेकर मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

भारत एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का विरल देश रहा है, जहां के जन जीवन में उदारता, सहिष्णुता, विचारों का खुलापन, बहस मुबाहिसा और शास्त्रार्थ युगों-युगों से रचे बसे हुए हैं। गणतांत्रिक परम्पराएं भारत में उस दौर से कायम हैं, जबकि अजातशत्रु के सामंती सम्राट के रूप में उदित होने से पूर्व भारतीय धरा पर अनेक गणतंत्र सदियों से अस्तित्व में रहे थे। महात्मा बुद्ध को जन्म भी एक ऐसे ही गणतंत्र में हुआ था, जिसे लिच्छवी गणतंत्र के तौर पर जाना जाता था। गणतांत्रिक मूल्यों को सीखने समझने के लिए भारत को कदाचित किसी की ओर देखना नहीं पड़ा। वैचारिक संकीर्णता और धर्मान्धता का प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कहीं कोई स्थान रहा ही नहीं। चिंतन परम्परा में वैचारिक मतभेदों को शत्रुता के तौर पर कदाचित निरूपित नहीं किया गया।

गणतंत्र में अहिंसक विरोध प्रदर्शन भी वस्तुतः राजसत्ता के कार्यकलापों और नीतियों के विरुद्ध सकारात्मक वैचारिक असहमति का परिचायक रहे हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वैचारिक आजादी और अहिंसक विरोध प्रदर्शन को बाकायदा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आजादी के आंदोलन के दौर में शानदार गणतांत्रिक विचारों और संस्कारों में दीक्षित कांग्रेस पार्टी ने सत्तानशीन होकर बहुत जल्द इन संस्कारों को विस्मृत कर दिया, जबकि 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की कयादत में सत्ता में आई विपक्ष की प्रथम प्रांतीय सरकार को बिना किसी ठोस कारण के बर्खास्त कर दिया गया। यह घोर अलोकतांत्रिक बर्खास्तगी पं. नेहरू काल में कांग्रेस हुकूमत में पनपी और पल्लवित हुई तानाशाही प्रवृत्ति के कारण हुई। 1975 में आपातकाल में लाखों लोग सिर्फ इसलिए जेलों में ठूंस दिया गया और लाखों को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने के लिए विवश कर दिया गया कि वे राजसत्ता के नीतियों का महज शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनमानस ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त देकर, उसे ऐतिहासिक सबक सिखाया।

भ्रष्टाचार का विश्व रिकार्ड कायम करने वाली मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले जनआंदोलन की प्रत्येक मुहिम को कुचल डालने का रुख अख्तियार कर चुकी है। मनमोहन सिंह सरकार के रवैये के कारण उच्चतम स्तर पर शासकीय भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए अण्णा हजारे की जनलोकपाल बिल की मुहिम का हश्र भी देश के समक्ष है। अकूत काले धन का राष्ट्रीयकरण करने की बाबा रामदेव की मुहिम का अंजाम तो देश ने अश्रुपूरित आँखों से टीवी के परदे पर देख ही लिया। क्या भारत के करोड़ों जन गण अनाचारी, भ्रष्टाचारी और जालिम हुकूमत की हिंसक शक्ति से खौफजदा होकर खामोश बैठ जाएंगे। साम्राज्य में सूर्यास्त न देखने वाली ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले भारतवासियों की संतानें इतनी निर्बल नहीं कि काले अंग्रेजों की राजसत्ता को शिकस्त न दे सकें। जातिवाद, धर्मान्धता और क्षेत्रीय संकीर्णताओं को दरकिनार कर जाग्रत होकर भारतीय नागरिक आम चुनाव के दिन ही सभी भ्रष्ट अपराधी और अहंकारी राजनेताओं को इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर सकते हैं।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)